(c) whether there was any call from the concerned States before the preparation of restructural proposal; and

(d) whether it would be introduced in the forth coming Parliament Session?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR) (a) and (b) yes, Sir.

(c) The decision to restructure the North Eastern Council was taken after the Prime Minister discussed the matter with the Chief Ministers of the States concerned,

(d) Yes, Sir.

Freedom Fighters Pension

869.PROF. RAM KAPSE:
SHRI RAM DEO BHANDARI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the State-wise and district-wise details of the applications pending in the country for freedom fighter's pension as on the 31st October, 1997;

(b) the maximum and the minimum periods of pendency and the reasons therefor;

(c) the number of applications approved in 1995-96, 1996-97 and till October 31, 1997 alongwith the State-wise and district-wise details regarding the results of the same; and

(d) the final decision likely to be taken regarding the remaining pending applications?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) A statement is enclosed as Annexure [*See Appendix* 182, *Annexure No.* 18]

(c) A statement is enclosed as Annexure [*See Appendix* 182, *Annexure No.* 18]

(d) While every possible effort is made to communicate the decision to the applicants in the shortest possible time. receipt and disposal of claims for pension being a continuous process. no definite time frame can be laid down for disposal of claims for pension.

इन्दिरा आवास योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए धनराशि

870. **प्रो राम बक्ष सिंह वर्मा:**
श्रीमती मालती शर्मा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इन्दिरा आवास योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि आबंटित धनराशि से निर्मित आवासों का उपयोग वास्तविक लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए धन में केन्द्रीय अंश की राशि इस प्रकार है–

1994–95 350.15 करोड़ रुपए
1995–96 1094.99 करोड़ रुपए
1996–97 1179.26 करोड़ रुपए

(ख) से (घ) इंदिरा आवास योजना के दिशा निर्देश के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करती है कि केवल सही लाभार्थियों का ही चयन हो। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टों के आधार पर कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी दौरा कर कार्यक्रम के क्रियान्वन की निगरानी करते हैं।

Safe drinking water for each village

871. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) how far the Eighth Five Year Plan target, of providing 5.83 lakh villages with at least one source of safe drinking water for each village or habitation, has been fulfiled:

(b) the number of villages and habitations

in each State and Union Territory still without a source of safe drinking water and the total estimated population of such villages; and

(c) the details of the action plan, if any, drawn out for implementation under the Ninth Plan for providing safe drinking water to each such village/habitation?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) As per 1991 Census, there were 5.87 lakh villages in the country. Against the target of providing safe drinking water facilities to 315,714 villages/habitations during the 8th Five Year Plan, the actual achievement was coverage of 339,705 villages/ habitations.

(b) The State-wise details of the non covered habitations are in the statement (see below). The total estimated population of such habitations as on 1.4.97 was 205.54 lakh.

(c) The State Governments have prepared action plans for providing safe drinking water to the non covered habitations by 1998-99 with some spill over in difficult areas to be covered by the year 2000 AD.

Statement

S.No.	State/UTs	Position of Not covered habitations as on 31.10.97
1.	Andhra Pradesh	198
2.	Arunachal Pradesh	838
3.	Assam	9603
4.	Bihar	3663
5.	Goa	36
6.	Gujarat	1575
7.	Haryana	45
8.	Himachal Pradesh	4835
9.	Jammu & Kashmir	3063
10.	Karnataka	2304
11.	Kerala	1145
12.	Madhya Pradesh	0
13.	Maharashtra	0
14.	Manipur	368
15.	Meghalaya	1201
16.	Mizoram	54
17.	Nagaland	464
18.	Orissa	2870
19.	Punjab	6229
20.	Rajasthan	9784
21.	Sikkim	0
22.	Tamil Nadu	0
23.	Tripura	969
24.	Uttar Pradesh	0
25.	West Bengal	767
26.	A&N Islands	11
27.	Dadra Nagar Haveli	128
28.	Daman & Diu	0
29.	Delhi	0
30.	Lakashadweep	0
31.	Pondicherry	0
	TOTAL:	50150

धर्मार्थ अथवा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से चल रही ग्रामीण विकास योजनाएं

872. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धर्मार्थ अथवा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता से चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) ऐसी योजनाओं के लिये किए गए वार्षिक बजट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं की निगरानी और समुचित कार्यान्वयन के लिये अपनाई गई विधि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु): (क) लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट), जो इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संगठन है, निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अथवा तदनुरूपी राज्य अधिनियम अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत न्यास अथवा धर्मार्थ और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:–

(1) जन सहयोग

(2) लाभार्थियों का संगठन

(3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना